संपादकीय

23 दिसंबर को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है और इसे 'किसान दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंसी सहकारी बैंकों की ाखाओं के द्वारा किसानों को ऋण देने के लिऐ करैंसी बिल जारी किऐ गऐ थे। अब जब किसान अपने ऋण चुकाना चाहते हैं तो बैंक उन्ही पुराने नोटों को लेने से मना कर रहे हैं। इस प्रकार किसानों को ऋण चुकाने से तार्किक रूप में मना कर देना चाहिऐ। हम सरकार से मांग करते हैं कि सहकारी बैंकों द्वारा जारी किसानों के सभी ऋणों को माफ कर दिया जाऐ। ऐसा न करने पर हमें कानूनी कार्यवाही का विकल्प तलाशना होगा।

नोटबंदी के बाद अधिकतम कृ-ि उपजों के मूल्य 30 प्रतिशत तक गिर चुके हैं और इससे किसान आहत हो रहे हैं। नोटबंदी को मिल रही प्रारंभिक समर्थन भी अब जवाब देने लगा है, क्योंकि सरकार दीर्घकालिक लाभ के वादे को न तो स्प-ट कर पा रही है और न ही दीर्घकालिक का अर्थ बता पा रही है। व-र्ा 2016 में नारा दिया गया था 'किसानों की दोगुनी आमदनी' और यह व-र्ा नोटबंदी की पीढ़ा से समाप्त हो रहा है। कृपया बेहतर व-र्ा 2017 की प्रार्थना करने और इस दिशा में कार्य करने के लिऐ हम सबको एकजुट होना चाहिऐ।

हमें 19 नवंबर, 2016 को माननीय वित्त मंत्री से बजट पूर्व वार्तालाप के लिऐ आमंत्रित किया था और हमारे द्वारा दिऐ गऐ सुझावों का विवरण नीचे दिया गया है। हम कृ-ाक समाज के सभी सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि इन सुझावों को अपने-अपने संसद सदस्यों के समक्ष रखें। कृपया इस वि-ाय पर हमें अपने विचार और सुझाव अथवा ट्रिप्पणी यथा शीघ्र भेजें।

'किसान दिवस'

नेत्र कौर और मीर सिंह के 5 बच्चों में सबसे बड़े चरण सिंह का जन्म सर्दियों के मौसम में 23 दिसंबर, 1902 को उत्तर-प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपूर में हुआ था। उनके माता-पिता ने उन्हें शिक्षा लेने के लिऐ विद्यालय में दाखिल कराया और वे अपनी एल.एल.बी. की डिग्री पूरी करने तक पढ़े, यह डिग्री उन्होंने 1926 में प्राप्त की। वकील के इस लाभकारी धंधे को छोड़कर उन्होंने सवतंत्रता आंदोलन में भाग लेने की प्रतिज्ञा की और व-र्ा 1929 में कांग्रेस दल के पूर्णकालिक सदस्य बन गऐ। इसी दल की ओर से उन्होंने भारत के हिंदी क्षेत्र के गढ़ में आम जनता की समस्याओं को सुलझाया।

26 जनवरी, 1930 को लाहोर में भारतीय रा-ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत से संपूर्ण रूप से स्वतंत्रता पाने के लिऐ 'पूर्ण स्वराज की घो-णा' की। व-र्ा 1930 के अंतिम समय में उन्हें 6 महीने के लिऐ जेल भेज दिया गया। उनके लगातार सक्रीय राजनैतिक कार्यों के कारण उन्हें कई बार जेल में जाना पड़ा। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेते हुऐ भी उन्हें 15 महीने जेल में बिताने पड़े।

मुगल भारत के भीतरी क्षेत्रों में नियंत्रण पाने के लिऐ जमींदारी पद्धति का उपयोग करते थे, ताकि वे सैनिक दलों को बनाऐ रखने के लिऐ राजस्व अर्जित कर सकें। अंग्रेजों ने भी इस ाो-ण पद्धति को बनाऐ रखा और

उनका सीधा सा ढ़ंग था कि उन्होंने जमींदारों के भूमि मालिकों के उनके अधिकार को पहचाना और इसके लिऐ किसानों से कर इकूटठा करने के लिऐ जिम्मेवारी ले ली और आम जनता को अपने वश में रखते थे। उत्तर-प्रदेश में राजस्व मंत्री के रूप में वे 'जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1951' की क्रांति के वे प्रमुख वास्तुकार थे।

उत्तर-प्रदेश में मंत्री के रूप में उनकी छवि एक स्प-टवादी की थी। इस कारण वे लोकप्रिय एवम् मजबूत जवाहर लाल नेहरू के इस प्रस्ताव पर भी असहमत थे कि उन्होंने सहकारी किसानों की रा-ट्रीय नीति सही नही बनाई थी, इसी विरोध के कारण उन्हें त्यागपत्र देना पड़ा। किसानों की समृद्धि उनका प्रमुख लक्ष्य था, जिससे वे कभी पीछे नहीं हटे और अपनी इसी ैली के कारण वे पूरे जीवन भर किसान नेता की प्रमुख विशे-ता के व्यक्ति बने रहे। उनका व्यक्तित्व एक स्प-ट व्यक्ति का था और अपनी बात को कभी घुमा-फिराकर नहीं कहते थे।

व-र् 1967 में चरण सिंह ने राज नारायण और राम मनोहर लोहिया के समर्थन से भारतीय क्रांति दल का गठन किया। वे 1967 में ही उत्तर-प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और दुबारा 1970 में भी मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पूरे भारत में कांग्रेस के विरोधियों को इकूटठा किया। उन्होंने अपनी लोकप्रिय जनसेवक की छवि के साथ लोगों का समर्थन जुटाया और सफलता प्राप्त की, किंतु वे सत्ता को बनाऐ रखने में कभी सफल नहीं हो पाऐ, क्योंकि वे किसी अनुचित बात पर समझौता नहीं कर सकते थे। चरण सिंह ने द्वितीय पंचव-ीय योजना में कुछ प्रमुखताओं का उल्लेख किया था जिन्हें लागू नहीं किया गया, भारत में लगातार गरीबी का यह मूल कारण था। यदि चरण सिंह के सुझावों पर अमल किया गया होता तो भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर होता और पी.एल. 480 तथा अनाज के आयात जैसी अपमानजनक घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ता।

वे न केवल एक विशि-ट गंभीर पाठक थे बल्कि उन्होंने कई अखबारों में भी लिखा और स्वंय पुस्तकें भी लिखीं। उनके बहुत से प्रकाशनों में कुछ हैः 'जमींदारी उन्मूलन (1947)', 'संयुक्त कृ-ि का एक्स-रेः समस्याएँ और इनके समाधान (1959), 'भारत की आर्थिक नीति - गांधीयन ब्लयूप्रिंट (1978) और भारत का आर्थिक दुःस्वप्न : कारण और समाधान (1981)'।

उन्होंने जवाहर लाल नेहरू की भारी उद्योग की समाजवादी सोच का विरोध किया। गांधी जी के मॉडल के प्रस्ताव का अनुसरण करते हुऐ उनका विचार था कि 'भवि-य में किसी भी ऐसे मध्यम या बड़े स्तर के उद्योग लगाने की अनुमति न दी जाऐ जो ऐसी वस्तुऐं और सेवाऐं उपल्बध कराता हो जिसे हमारे लघु और छोटे उद्योग उपल्बध करा सकते हैं या तैयार कर सकते हैं'।

अंग्रेजी राज से ही भारत की स्वतंत्रता के बाद भी किसानों के जीवन में दशकों पुराने सुधार की धीमी गति से वे निराश थे और इसी दिशा में उन्होंने किसानों के सुधार के लिऐ भरसक प्रयास किऐ किंतु व-र् 1985 में उन्हें हृदय रोग के कारण इस अभियान को रोकना पड़ा। उन्होंने किसानों की दुर्दशा के लिऐ ाहरों पर केंद्रित नीतियां तैयार करने के लिऐ सफेद कॉलर वाली नौकरशाही, उच्च जाति और पूंजीवादियों को जिम्मेवार ठहराया। इसी कारण से समाजवादी और नए उदारवादी लोग एक नए सामान्य किसान को नीति निर्माताओं की मेज पर बैठाने पर कभी सहमत नहीं हुऐ। यह केवल एक बाजीगरी ही कहेंगे की उन्हें हमेशा जाटों का नेता माना गया और यही कहा जाता रहा कि वे केवल जाटों का ही समर्थन करते हैं, जबकि वास्तविकता यह

थी की जवाहर लाल नेहरू कश्मीरी ब्राहमणों की बैठकों में लगातार भाग लेते थे, किंतु चरण सिंह ने जाटों की किसी एक भी बैठक में भाग नहीं लिया, बल्कि जाटों की विशे-ा और सही मांगों के लिऐ अकेले ही बोलते थे। व-र् 1954 में उन्होंने राजपत्रित नौकरियों के लिऐ आरक्षण का प्रस्ताव रखा, जिसके अंतर्गत केवल उन्हीं लोगों को नौकरियां प्रदान की जानी थीं जो अपनी ही जाति के अतिरिक्त किसी अन्य निम्न जाति में विवाह करे।

जब जातिवाद का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया तो अधिकारी और नौकरशाहों ने उन पर केवल अमीर किसानों और बड़ी-बड़ी जमीन रखने वालों के हितों की बात कहने का आरोप लगाया। दूसरी ओर जब जमींदार अधिकतम भूमि के स्वामी थे, तो उन्होंने अकेले ही उनके एकाधिकार को तोड़ने का प्रयास किया।

एक विशे-ा पड़े-लिखे वर्ग, अधिकारियों, नौकरशाहों, मीडिया और व्यापारिक घरानों के लगातार आरोप लगाने से चरण सिंह की हस्ती मिट चुकी होती यदि उन्होंने कड़ा परिश्रम, नि-ठा और ईमानदारी न अपनाई होती। चरण सिंह एक साधारण व्यक्ति थे और उन्होंने अपने बालों को कभी लंबा नहीं किया क्योंकि वे किसी भी प्रकार के दिखावे या प्रसाधनों के विरूद्ध थे। उनके वस्त्रों में धोती और गांधी टोपी का विशे-ा महत्व था। उन्होंने नहाने के लिऐ कभी साबुन का उपयोग नहीं किया और अपने दांतों को साफ करने के लिऐ नीम की दातुन करते थे। वे सादा खाना ही खाते थे और मदिरा तथा धुम्रपान से घृणा करते थे। वे आर्य समाज के आदर्शों के पक्के विश्वासी थे जिसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने रूढ़िवादी हिंदु धर्म में सुधार के लिऐ आरंभ किया था।

आपातकाल लगाने के समय इंदिरा गांधी द्वारा कई नेताओं को 1 व-र् से अधिक जेल में रखा गया था, उनमें से एक चरण सिंह भी थे। इसके पश्चात व-र् 1977 में इंदिरा गांधी को हराने के लिऐ उन्होंने विपक्ष का नेतृत्व किया। चरण सिंह के नेतृत्व में भारतीय लोक दल के संसद सदस्यों ने सबसे अधिक स्थान जीते और उसके पश्चात जनसंघ ने जीते। चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के लिऐ छोटे से जनसंघ दल ने जगजीवन राम के नाम का प्रस्ताव दे दिया जो कि चरण सिंह की प्रतिक्रिया के ही अनुरूप था। उन्होंने सदा उनका ही विरोध किया था जिन्होंने आपातकाल लगाने के प्रस्ताव पर सहमति दी थी। जनसंघ के बिछाऐ जाल में गिरने से स्थिति ऐसी उत्पन्न हुई की मोरारजी देसाई के नाम पर आम सहमति बन गई।

उप-प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें गृहमंत्री बनाया गया और चरण सिंह ने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने की बहुत बड़ी गलती कर दी। जनता दल का प्रयोग असफल सिद्ध हुआ, छोटे-छोटे मतभेद उभरकर सामने आ गए, जब चरण सिंह ने मोरारजी देसाई के बेटे के स्कैंडल की जांच करने पर जोर दिया। इस प्रकार उन्हें अनौपचारिक रूप से मंत्री पद से हटा दिया गया।

मोरारजी देसाई सरकार को गिराने का अवसर मिलने के कारण इंदिरा गांधी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिऐ सहमत हो गई। इंदिरा गांधी की राजनीति से पूर्ण अवगत होते हुऐ भी वे प्रधानमंत्री बनने पर सहमत हो गऐ। वे इस तथ्य को जानते थे कि किसान समुदाय से उनकी पकड़ ढ़ीली पड़ रही है और समय भी उनका साथ नहीं दे रहा है। इस कारण उन्होंने सोचा कि किसानों को और उनकी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दें तथा उच्च जाति और ाहरी वर्ग की चालों से उन्हें बचाया जाऐ। वे अपने लक्ष्य में तो सफल हो गए, कि ग्रामीण भारत से एक किसान भी प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच सकता है।

किंतु, इतिहास को तो ृाहरों का शिक्षित वर्ग ही लिखता है, जिसमें यही लिखा गया कि चरण सिंह सत्ता के भूखे थे। लेकिन वास्तव में तथ्य यह है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी द्वारा समर्थन के लिऐ उन्हें धन्यवाद देने के लिऐ उनके पास जाने से मना कर दिया था। इंदिरा गांधी द्वारा दिया गया समर्थन जनता सरकार को गिराने के लिऐ ही था। अपने सिद्धांतों और दो-ाी होने में से किसी एक को चुनने के लिऐ उन्होंने कुछ सप्ताह के भीतर ही प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया। कांग्रेस दल द्वारा दिऐ गऐ समर्थन के बदले में उन्होंने उनकी ृार्तें मानने से इंकार कर दिया था।

चरण सिंह 'चौधरी साहब' के नाम से लोकप्रिय थे और वे देश के किसानों के सबसे बड़े नेता था जिन्होंने 29 मई, 1987 को अंतिम सांस ली ओर ऐसा ून्य छोड़ गऐ जो अभी तक भरा नहीं जा सका। किसान वर्ग आज भी अपनी दयनीय स्थिति से निकलने के लिऐ एक ऐसे नेता के इंतजार में है। उनके देहांत के बाद ग्रामीण राजनीति का दृश्य पहचाना ही नहीं जाता। राजनीति की धूरी का केन्द्र समाज के नेतृत्व को छोड़कर जातिवाद राजनीति की ओर परिवर्तित हो चुका है। जीवन भर उन्हें गलत रूप से निशाना बनाया गया, उन्होंने एक बार कहा था 'यह दु-प्रचार अपने आप समाप्त हो जाएगा जब चरण सिंह नहीं रहेगा'। वे गलत थे उनकी कमी आज भी महसूस की जाती है विशे-ाकर किसान समुदाय में।

बजट सुझाव

दिनाँकः 19 नवम्बर, 2016

प्रिय श्री जेतली जी,

भारत कृ-ाक समाज एक गैर सांप्रदायिक किसान संगठन है जो भारतीय किसानों की समृद्धि पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता की सिफारिश करता है।

कई दशकों से हमारा देश इस वि-ाय को लेकर भयभीत है कि हम अपने देश की जनता का ही पेट भरने में असमर्थ हैं। बजट आबंटन सहित कृ-ाि क्षेत्र के लिऐ हमारी नीतियों में एक ही वायदा किया जाता है कि खाद्य उत्पादन बढ़ाया जाऐगा। अब इसे बदलने का समय आ गया है, इसे अब संपूर्ण प्रगति और किसानों की समृद्धि की कृ-ाि नीति तैयार करनी चाहिऐ। एक ऐसी खाद्य पद्धति जिसमें पर्याप्त न्यूट्रिशन उपलब्ध हों और उगाऐ जाने वाली प्रत्येक उपज ृद्ध हो। 2017 के पूर्व बजट के लिऐ हमारे निम्नलिखित सुझाव हैंः

1. नोटबंदी की चिंताओं को समाप्त करने पर तुरंत ध्यान दिया जाऐ। जिला सहकारी बैंकों पर पुराने नोट बदलने और जमा कराने का प्रतिबंध तत्काल हटाया जाऐ। यह कार्य उन ृाखाओं में किया जा सकता है जो भारीतय रिजर्व बैंक की प्रणाली से संबद्ध है। कृ-ाि उत्पाद विपणन समितियों की मंडियों में नकदी की उपलब्धता 15 प्रतिशत तक प्रति सप्ताह बढ़ानी चाहिऐ ताकि दुकानदार अपनी साप्ताहिक औसत कमाई को पिछले वित्त व-र् में ही विपणन समितियों के खातों में रिकॉर्ड करा सके। इससे न-ट होने वाले फल और सब्जियों की बिक्री में तेजी आएगी।
2. मसौदा जी.एस.टी. बिल में विसंगतियों को तुरंत हटाया जाऐ (अलग से भेजा गया)।
3. व-र् 2014-15 से अधिक कृ-ाि क्षेत्र के लिऐ व्यय बढ़ाया जाऐ। उल्लेखनीय है कि व-र् 2015-16 का आबंटित बजट व-र् 2013-14 से भी कम था।
4. कृ-ाि क्षेत्र के सकल घरेलू उत्पाद में कृ-ाि अनुसंधान और विकास में 2 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया जाऐ।
5. कृ-ाि विस्तार में सुधार। एक 5 व-र्ीय योजना बनाएँ कि प्रत्येक 10 गांव के लिऐ एक्सटेंशन वर्कर के रूप में एक कृ-ाि स्नातक की नियुक्ति करें : इसके लिऐ 60,000 रिक्त स्थान बनाऐं।
6. आंकडे संकलन और मूल्यांकन के लिऐ 10 गुना निधि बढ़ाई जाऐ। सरकार को एक रा-ट्रीय नियमित डाटाबैस तैयार करना चाहिऐ, जो सभी भागीदारों को नाम मात्र मूल्य पर मिल सके।
7. सभी में संसाधनों का एक समान वितरण, चाहे उनके पास भूमि का आकार कैसा भी हो, इसे 2 हैक्टेयर कृ-ाि के लिऐ गणना की जाऐ (किसान परिवार की महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधा भुगतान)।

8. संतुलित उर्वरक के उपयोग को प्रोत्साहन, यूरिया के मूल्य बढ़ाऐं और दूसरी और पी. ऐंड के. उर्वरक के मूल्य कम करें ताकि किसानों या सरकार पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।
9. आय अर्जित करने के लिऐ 'कृ-ि-वन-उत्पाद' पर बल दिया जाऐ।
10. पशुपालन के क्षेत्र में पैसा देते समय निवारक उपायों पर विशे-ा ध्यान दिया जाऐ, जैसा एन. डी.डी.बी. और अमूल द्वारा किया जा रहा है, न कि बीमारीयों का ईलाज करने पर।
11. गोशाला के लिऐ पैसा दिया जाऐ लेकिन उसमें ार्त रखें की उस बैड़े में कुल पशुओं की संख्या का 40 प्रतिशत भाग नर पशुओं का हो।
12. बिजली उत्पादन के लिऐ प्रोत्साहन की सीमा कम न करते हुए जैविक गैस एककों के लिए अधिक आर्थिक सहायता दी जाऐ।
13. कृ-ि मशीनरी पट्टे पर देने की सेवा को प्रोत्साहित करना ताकि किसान अच्छी कृ-ि मशीनरी का उपयोग बिना इसकी खरीद के कर सके। कृ-ि मशीनरी योजना की मशीनों को आगे देने की योजना का दुरूपयोग और इसकी ार्तों में बार-बार परिवर्तन को रोका जाऐ।
14. कई समाचार पत्रों में खबर छपी है कि किसानों ने करोड़ों रूपऐ की आय की घो-णा की है। हमारा सुझाव है कि उन सभी नागरिकों की आयकर विवरिणी की आयकर विभाग जांच करे जिन्होंने रू. 10 लाख से अधिक कृ-ि आय की घो-णा की है।
15. किसान उपभोक्ता की आवश्यकता और मांगों पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। करों से उपभोग की प्रणाली में परिवर्तन हो सकता है। अतः यह अनिवार्य है कि अस्वस्थ खाने पर टैक्स लगाया जाऐ (जिनमें अधिक चीनी और नमक हो, जिनसे स्वास्थ्य देखभाल की लागत में वृद्धि होती है)। इस धन को दीर्धकालिक कृ-ि प्रणालियों का उपयोग करने के लिऐ खर्च किया जाऐ।
16. परम्परागत कृ-ि विकास योजना जैविक कृ-ि में सुधार लाती है। इसमें 10 गुना अधिक व्यय किया जाऐ और निजी कृ-ि क्षेत्र में विविध फसलें उगाने के लिऐ विशे-ा प्रोत्साहन दिया जाऐ।
17. आरंभ में खेतों में रसायनिक उपयोग का लक्ष्य 10 प्रतिशत कम किया जाऐ। नकली और मिलावटी कीटनाशकों की जांच के लिऐ प्रयोगशाला स्थापित की जाऐं। इसके अतिरिक्त, उन प्रयोगशालाओं को पैसा दिया जाऐ जो ताजे और प्रसंसाधित खाद्य वस्तुओं की जांच कर सके।
18. कृ-ि प्रसंसाधन प्रोत्साहन केवल छोटे और मझौले किसानों को ही दिया जाऐ और इनमें से भी जो ऐफ.पी.ओ. के हैं, उन्हें प्रमुखता दी जाऐ। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार मिलेगा और किसानों की आय में भी वृद्धि होगी।
19. एक स्थाई कर ढ़ांचे सहित दीर्घकालिक कृ-ि आयात-निर्यात नीति की आवश्यकता है। ताजी कृ-ि वस्तुओं पर अधिकतम आयात ुल्क लगाया जाऐ। कृ-ि जिंसों के निर्यात पर कोई प्रतिबंध न हो।
20. 'स्टॉर्ट अप इंडिया' मिशन के अंतर्गत दिऐ जाने वाले सभी प्रोत्साहन किसान उत्पादक संस्थाओं (ऐफ.पी.ओ.) को भी दिया जाऐ और इन्हें कर में छूट तथा इनके लिऐ पूंजी और आधारभूत सुविधाओं का प्रावधान भी किया जाऐ। हालांकि किसानों की कृ-ि आय पर आयकर में छूट दी गई है लेकिन पहले वर्-ा से ही कृ-ाक उत्पाद संस्थाओं की आय पर उन्हें कर देना होता है - यह किसानों के लिऐ बहुत बड़ी हानि है इस कारण वह सामूहिक व्यवसायिक कंपनी का गठन नहीं कर पाते। इस कार्य के लिऐ रू. 3,000 करोड़ आबंटित किऐ जाऐं।
21. अभी भारत 70 प्रतिशत से अधिक खाद्य तेलों का आयात कर रहा है और हर वर्-ा यह मात्रा बढ़ रही है। इससे दोहरी हानि हो रही है, आपूर्ति कम और खाद्य तेलों के मूल्य बढ़ रहे हैं। इस कारण कुक्कुट पालन और पशुपालन की लागत बढ़ती जा रही है। इसका उपाय है, खाद्य तेलों पर अधिक ुल्क लगाऐं ताकि किसान तिलहनों की पैदावार बढ़ाने के लिऐ प्रेरित हों। दालों और तिलहनों

के लिऐ न्यूनतम समर्थन मूल्य कारगर ढंग से लागू किया जाऐ और इसके लिऐ व-र्ा 2016-17 (न्यूनतम समर्थन मूल्य की सामाजिक और पर्यावरण समानता) के आर्थिक सर्वेक्षण में दी गई न्यूनतम समर्थन मूल्य की नई प्रक्रिया को लागू किया जाऐ ताकि देश में दालों और तिलहनों के अधिक उत्पादन के लिऐ इस प्रकार के विभिन्न उपाय किऐ जा सकें।

22. सिंचाईः

(क). सभी वर्तमान सिंचाई परियोजनाओं की मरम्मत और रखरखाव के लिऐ पैसा दिया जाऐ। विद्यमान सिंचाई क्षेत्रों के लिऐ नालियां बनाई जाऐं। नई बाढ़ सिंचाई परियोजनाओं को कोई फंड नहीं दिया जाऐ।

(ख). प्रधानमंत्री कृ-ि सिंचाई योजना के अंतर्गत वॉटरशेड़ मैनेजमैंट के लिऐ बजट 10 गुना बढाऐं और इसमें भी व-र्ा आधारित क्षेत्रों पर विशे-ा ध्यान दिया जाऐ।

(ग). सभी किसानों को भूमि की नमी मापने के सेंसर वितरित किऐ जाऐं। इसके अतिरिक्त 10 लाख छोटे-छोटे जल भंडारण टैंकों के निर्माण के लिऐ पैसा दिया जाऐ।

(घ). प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में आधारभूत नाम और सूक्षम सिंचाई उद्योग के द्वारा सहयोग देकर इन क्षेत्रों और उद्योगों को सभी ुल्कों और करों से मुक्त किया जाऐ।

(ड़). सोलर पंपों की प्रणाली पर आर्थिक सहायता दी जाए और व्यक्तिगत किसानों, सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं को भी बढ़ावा दिया जाऐ। आज 50,000 की तुलना में 2,50,000 सोलर पंपों का बजट प्रावधान किया जाऐ।

(च). वर्तमान में सिंचाई और कृ-ि विभागों द्वारा उत्पन्न किया जा रहा आधारभूत ढांचा बिना एक दूसरे की जानकारी के होता है या एकांत रूप में होता है। अतः अनुरोध है कि योजना और विभागों के कार्यों में मूलभूत परिवर्तन लाऐ जाऐं।

23. ऋणः

(क). रू. 2 लाख तक ऋण लेने वाले किसानों की संख्या दोगुनी की जाऐ और केवल 1 प्रतिशत ब्याज लिया जाऐ। इस प्रकार के ऋण खातों को आधार से जोडें ताकि डुपलिकेशन से बचा जाऐ। ब्याज छोडने की योजना से सहायता नहीं मिल पाती अतः इसे समाप्त कर दिया जाऐ।

(ख). संस्थागत ऋण छोटे किसानों तक नहीं पहुंचते। सुधारात्मक उपायों की घो-णा करें। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा दिऐ गऐ कृ-ि ऋण के संपूर्ण विवरण की सी.ए.जी. से लेखा परीक्षा कराने का आदेश दें।

(ग). किराऐ अथवा पट्टे पर खेती करने वाले किसानों को बैंक लोन नहीं देता है। उन्हें ऋण मिलना चाहिऐ। भूमिहीन किसान ऋण योजना और नीति आयोग की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुऐ यह आवश्यक है कि पट्टे पर खेती करने वाले किसानों की सहायता की जाए, इसके लिऐ हमारा प्रस्ताव है कि एक ऋण गारंटी नीधि बनाई जाऐ ताकि बैंकों का ऐसे लोगों को ऋण देने के प्रति विश्वास बढ़े, यह ऋण भूमिहीन किसानों, किंतु लाईसेंस धारी किसानों को व्यक्तिगत किसानों और संयुक्त देयता समूह दोनों के रूप में मिलना चाहिऐ। ऐसी नीधि तैयार करने की आवश्यकता है और व-र्ा 2017-18 के लिए लगभग रू. 5,000 करोड़ अलग से रखे जाऐं।

24. मंडियां (मार्केटस):

(क). किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिऐ नीति आयोग द्वारा सुझाई गई 'मूल्य कमी भुगतान प्रणाली' को तत्काल लागू किया जाना चाहिए।

(ख). विपण हस्तक्षेप योजना और मूल्य स्थाई निधि के अंतर्गत अधिक फसलें ामिल करें। इसके लिऐ रू. 5,000 करोड़ की वृद्धि करें।

(ग). सार्वजनिक वितरण प्रणाली का उपयोग दालों और बाजरे की खरीद के लिए भी किया जाए ताकि निर्धन उपभोक्ताओं के अनाज में वृद्धि हो सके और किसान भी विविधिकरण के प्रति प्रोत्साहित हों।

(घ). कृ-ि बाजार मंड़ियों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने और वर्तमान सभी कृ-ि मंडियों को संपूर्ण आधारभूत सुविधाऐं देने के लिए निधियों में वृद्धि करें।

(ड़). किसानों की फसलों के विपणन के लिए नियमित मंडियों (ए.पी.एम.सी.) में जाने की ृार्त को तुरंत हटाया जाऐ और प्राईवेट मंडियों और किसानों की मंडी में भी उपभोक्ताओं को सीधे बिक्री करने के लिऐ प्रोत्साहित किया जाना चाहिऐ।

(च). मंडियों का ुल्क कम करना और बिचौलियों को हटाया जाना अनिवार्य है। मंडियों का ुल्क हटाने या कम करने से राज्य सरकारों की आय में कमी आएगी अतः वे इसका विरोध करेंगी, इसके लिऐ 5 व-र् तक उन्हें इनकी क्षति की पूरी भरपाई या कुछ भाग की भरपाई करने पर विचार किया जाऐ।

25. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग को अधिक पैसा दिया जाऐ, विशे-कर कृ-ि क्षेत्र हेतु मौसम की स्टीक भवि-यवानी में नवीनता लाने के लिऐ।

26. प्राकृतिक आपदा द्वारा किसानों को हानि पहुंचाना अब वार्-िक घटना बन चुकी है, हालांकि यह देश के अलग-अलग भागों में अलग-अलग समय पर आती है। अतः एस.डी.आर.एफ. / एन.डी. आर.एफ. के फंड में पर्याप्त वृद्धि की जाऐ। किसानों को आपदा राहत के लिऐ बजट में आबंटन को बढ़ाकर कम से कम रू. 25,000 करोड़ किया जाना चाहिऐ।

27. चावल गहनता की प्रणाली को भी प्रोत्साहित करने के लिऐ अधिक पैसा जारी किया जाऐ।

28. 7वें वेतन आयोग को देखते हुऐ संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों की आय में व्यापक वृद्धि हो चुकी है जबकि किसानों की आय या तो स्थाई रहेगी अथवा कम भी हो सकती है (मुद्रा स्फीति को देखते हुऐ)। इसके लिऐ एक स्थाई सांविधिक किसानों की आय का आयोग बनाया जाऐ ताकि सभी किसान परिवारों के जीवनयापन की मूल आय सुनिश्चित हो सके। एक किसान आय गारंटी अधिनियम भी बनाया जाऐ। व-र् 2017-18 के लिऐ बजट में प्रावधान किया जाए ताकि कृ-ि आय आयोग का गठन हो सके और एक संस्था बन जाए जिससे व-र् 2018-19 से किसानों को संपूर्ण आय सुरक्षा का कवर मिल सके।

29. घरों में भी कुछ इस प्रकार की प्रणाली स्थापित करने का व्यापक कार्यक्रम बनाया जाऐ ताकि घर में ही पौ-ि्टक तत्वों वाले खाने की उपलब्धता हो सके।

30. जैविक विविधता के संरक्षण और इसे बनाऐ रखने के लिए भी निधि आबंटित की जाऐ। पंचायतों को सीधा पैसा इस ृार्त के साथ दिया जाऐ कि पंचायतें 10 एकड़ जैविक विविधिता के क्षेत्र में तंत्र स्थापित करेंगी।

31. किसानों की आय बढ़ाने के लिऐ उन्हें महंगी कृ-ि जिंसों का उत्पादन करने के लिऐ प्रोत्साहित किया जाऐ ताकि वे फल और अन्य महंगी फसलें, डेरी उत्पाद, कुक्कुट पालन, सूअर पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन आदि जैसे कार्यों की ओर प्रेरित होंगी।

32. जब ृाहरी नवीकरण अथवा स्मॉर्ट सिटी के लिए पैसा दिया जाऐ तो इन ृाहरों के लिऐ एक अनिवार्य ृार्त रखी जाऐ की वे जनसंख्या के घनत्व के आधार पर आवासीय क्षेत्रों में किसानों की मार्किट के लिऐ भी स्थान आबंटित करें।

33. बजट में यह संकल्पना भी रखी जाए कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ृाहरी सुविधाऐं प्रदान की जाऐं ताकि किसानों के जीवन का स्तर भी सुधरे और जो गांव और ृाहरों के बीच की दूरी है वो कम हो।

स्मॉर्ट सिट्रीज के लिए पैसा खर्च करने के स्थान पर हमारा सुझाव है कि 4,000 स्मॉर्ट जनसंख्या नगरों को पैसा दिया जाए।

कृ-ि क्षेत्र को बचाने के लिऐ अति आवश्यक है कि गैर कृ-ि रोजगारों को उत्पन्न किया जाए ताकि भारतीय जनसंख्या का एक-तिहाई भाग से अधिक कृ-ि पर निर्भर न रहे। पहले की पाई गई हमारी उपलब्धियां ही आज हमारी सबसे बड़ी चुनौतियां बन चुकी हैं। हम इन्हें बदल तो नहीं सकते लेकिन परिवर्तन करने के लिऐ प्रयास अवश्य कर सकते हैं।

आदर सहित,

भवदीय,

(अजय वीर जाखड़)

श्री अरून जेतली,
माननीय वित्त मंत्री,
भारत सरकार,
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-110001